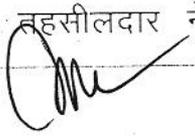


राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ  
प्रकरण क्रमांक निगरानी 757 -दो/15 जिला शाजापुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
7-4-15	<p>यह निगरानी म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन के अपील प्रकरण क्रमांक 439/13-14 में पारित आदेश दिनांक 02-03-2015 से असन्तुष्ट होकर प्रस्तुत की गयी है।</p> <p>2/ मैने प्रकरण के अभिलेख का अवलोकन किया तथा आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया। आवेदकगण के अभिभाषक का तर्क है कि तहसीलदार ने स्थल निरीक्षण किये बिना आदेश पारित किया गया है। देवकरण विरुद्ध खुमानसिंह आदि में प्रकरण क्रमांक 4/अ-13/87-88 में पारित आदेश दिनांक 07-11-94 द्वारा आवेदकगण का रास्ता खोला गया था जिसके विरुद्ध सक्षम न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाने से वह अंतिम हो चुका है और अनावेदकगण का आवेदनपत्र रेस-जूडिकेटा के सिध्दान्त के अनुसार तहसील न्यायालय में प्रचलन योग्य नहीं था। अतः उन्होंने निगरानी ग्राह्य करने का अनुरोध किया।</p> <p>3/ नायब तहसीलदार ने अपने आदेश दिनांक</p>	



11-9-13 में यह निष्कर्ष निकाला गया है कि अनावेदकगण, इस प्रकरण में आवेदकगण, ने सर्वे क्र० 2906 पर मुरम पत्थर डालकर मान. न्यायालय द्वारा सुखाधिकार के आदेश का उल्लंघन किया है, अनावेदकगण केवल उक्त जगह से फसल आदि ला ले-जा सकते हैं, मुरम पत्थर डालकर निर्माण नहीं कर सकते हैं। अतः नायब तहसीलदार द्वारा आवेदकगण पर संहिता की धारा 132 के तहत पाँच हजार रूपये से दण्डित करते हुए सम्पूर्ण मुरम, पत्थर स्वयं दो दिवस में हटाने के आदेश दिये हैं। इस आदेश को दोनों अपीलीय न्यायालयों अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त ने अपने आदेश दिनांक क्रमशः 07-05-14 एवं 02-03-15 द्वारा यथावत रखा गया है। मैंने प्रकरण में प्रस्तुत आदेश दिनांक 07-11-94 की फोटो प्रति का भी अवलोकन किया। यह प्रकरण संहिता की धारा 131 के अन्तर्गत देवकरण विरुद्ध खुमानसिंह के विरुद्ध चला जिसमें नायब तहसीलदार द्वारा यह निष्कर्ष निकाला गया है कि आवेदक पक्ष ने साक्ष्य या प्रमाण द्वारा ऐसे कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये हैं जिससे कि वादग्रस्त मार्ग रूढ़िगत होने संबंधित विनिश्चयन किया जा सके। स्थल निरीक्षण के समय पायी गई वस्तुस्थिति को देखते हुए मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि वादग्रस्त मार्ग से अनावेदक पक्ष अपनी कृषि भूमि पर कृषि कार्य हेतु उपयोग यथावत करते रहे। इससे स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन रास्ते का कृषि कार्य हेतु उपयोग करने के

आदेश पूर्व में नायब तहसीलदार द्वारा दिये गये थे, किन्तु इस आदेश का उल्लंघन करने से अनावेदक के आवेदनपत्र के आधार पर विधिवत कार्यवाही करने के पश्चात आवेदकगण पर तहसील न्यायालय द्वारा पाँच हजार रूपये अर्थदण्ड आरोपित करते हुए मुरम व पत्थर हटाने के आदेश दिये हैं जिसे दोनों अपीलीय न्यायालयों द्वारा यथावत रखा गया है। ऐसी दशा में निगरानी आवेदन ग्राह्य करने का पर्याप्त आधार नहीं है।

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी आवेदन खारिज किया जाता है। अपर आयुक्त का आदेश दिनांक 02-03-15 तथा अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश यथावत रखे जाते हैं। पक्षकार सूचित हों। अधीनस्थ न्यायालयों को आदेश की प्रति भेजी जाय तथा राजस्व मण्डल का अभिलेख दाखिल अभिलेखागार किया जाय।

  
(एम० के० सिंह)  
सदस्य

